बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 186 ● नई दिल्ली ● शनिवार 09 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 8 करोड़ ठगे, दिल्ली में अंतरराज्यीय गिरोह के 14 जालसाज दबोचे

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में साइबर ठगी के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि यह गिरोह टेलीग्राम के जरिए संगठित तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहा था। डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 को गीता कालोनी स्थित एक होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां से अलग-अलग राज्यों के 12 आरोपितों को पकड़ा गया। पूछताछ और जांच के दौरान गिरोह के दो अन्य सदस्यों को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई।

अमेरिका ने सीजफायर तोड़कर ईरान पर फिर बमबारी की

तेल अवीव । अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीजफायर के बीच यह कार्रवाई की। दरअसल, अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रम्प ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें हमने उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया और उनकी कई छोटी नावों को डुबो दिया। हम उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देंगे और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं। वहीं, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने कहा है कि होर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20 हजार नाविक भी फंसे हुए हैं।

केरल- सीएम पद की लड़ाई सड़कों पर आई; पर्यवेक्षकों ने खरगे को सौंपी रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरल के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी है। इसी बीच, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के समर्थक सड़कों और सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। एआईसीसी के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन गुरुवार को जब कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में शामिल होने और पार्टी के 63 विधायकों से अलग-अलग बातचीत करने पहुंचे, तब तिरुवनंतपुरम स्थित इंदिरा भवन के पास सांसद केसी वेणुगोपाल के समर्थन में छह बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए। वेणुगोपाल ने केरल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। तिरुवनंतपुरम में लगाए गए वेणुगोपाल के एक फ्लेक्स बोर्ड पर गुरुवार को कथित तौर पर ग्रीस ऑयल फेंक दिया गया।

वीडी सतीशन के समर्थन में प्रदर्शन

दूसरी ओर, राज्य के कई हिस्सों में वीडी सतीशन के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा, अलप्पुझा और कन्नूर जिले के इरिकूर में वेणुगोपाल के खिलाफ और सतीशन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। हालांकि, फ्लेक्स बोर्ड की इस लड़ाई में रमेश चेन्निथला काफी पीछे दिख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि वेणुगोपाल को अधिकांश विधायकों का समर्थन

हासिल है। लेकिन पार्टी नेताओं ने इस बारे में कोई सीधा बयान नहीं दिया है। इसके बजाय सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया से बातचीत के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिए जा रहे हैं।

विधायक दल ने शीर्ष कमान को दिया सीएम चुनने का अधिकार

नवनिर्वाचित विधायकों के दल ने एक प्रस्ताव पारित कर एआईसीसी अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है। यही नेता आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बनेगा। ऐसे में यह त्रिकोणीय मुकाबला अब

अब दिल्ली में होगा फैसला

नई दिल्ली और पार्टी मुख्यालय तक पहुंचने की संभावना है।

उम्मीद है कि पर्यवेक्षक शुक्रवार को एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद अंतिम चर्चा के लिए केरल के नेताओं को पार्टी मुख्यालय बुलाया जा सकता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी। हालांकि, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सहयोगी दलों में ज्यादातर वीडी सतीशन को पसंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अजय माकन ने कहा, आज हमने कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। आज हमने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी। नवनिर्वाचित विधायक दल (सीएलपी) की बैठक ने एक-लाइन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया और उस प्रस्ताव की एक प्रति भी सौंप दी गई। हमने विधायकों से एक-एक करके बात की और उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे नोट कर लिया। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि कई लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। हमने उसे नोट कर लिया है और हाई कमान को सौंप दिया है।

टीआरई -4 अभ्यर्थियों पर चला पुलिस का डंडा! जेपी गोलंबर पर मचा हंगामा, कई छात्र घायल

पटना । पटना में TRE 4 के विज्ञापन जारी करने और बीपीएससी नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई हुई है।

पटना कॉलेज से निकला गया विरोध मार्च जब जेपी गोलंबर पहुंचा, तो वहां बड़ी संख्या में जुटे हजारों अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में अभ्यर्थी लगातार परीक्षा प्रक्रिया में देरी का विरोध कर रहे थे और जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। छात्र पटना कॉलेज से निकलकर बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया गया। इस दौरान कुछ छात्र नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है।

अभ्यर्थियों की मांग और आंदोलन

छात्र नेता दिलीप ने कहा कि TRE 4 के लाखों अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष से शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि 10-15 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी, जबकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया था। दिलीप कुमार ने कहा कि एक ओर सरकार TRE 4 की वैकेंसी की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी अधियाचना मिलने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो पटना में फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

बीपीएससी नोटिस और आरोप

बीपीएससी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक नोटिस जारी कर कहा था कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र ही TRE 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि बार-बार TRE 4 के अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। विज्ञापन के इंतजार में हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होती जा रही है।

घुसपैठ, गो तस्करी असंभव होगी- शाह ने बता दिया बंगाल सरकार का एजेंडा, दीदी पर कसे तंज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए। वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। नाम के एलान के बाद विधायक दल को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इतना बड़ा विधायक दल देखकर मन, आत्मा, शरीर, सबके अंदर खुशी की लहर उठती है। मैं दोनों हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।

अमित शाह ने कहा जिस तरह का माहौल सीपीआईएम के समय से यहां बनाया जाता था, ममता ने इसे और गहरा भय में बदला। यहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, बर्बरता के थे। उसके बीच भाजपा पर भरोसा करके बंगाल की जनता को प्रचंड विजयी देने के लिए धन्यवाद। बंगाल की जनता ने जो अपेक्षाएं रखी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे को थोड़ा भी ठेस न पहुंचे। अमित शाह ने कहा हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है, हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। अमित शाह ने आगे कहा, त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में भाजपा सरकार है अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। अब घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस क्षेत्र को सुरक्षा के अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करेगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में हराया था। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपको आपके घर में हराया है। भवानीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद। इस जीत का महत्व पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इसका महत्व भाजपा-एनडीए का 21वां राज्य हुआ तक सीमित नहीं है।

23 में से 9 जिलों में तृणमूल का खाता नहीं खुला- अमित शाह

अमित शाह ने कहा –चुनाव परिणामों में राज्य के 23 प्रशासनिक जिलों में से नौ जिले ऐसे हैं, जहां दीदी का खाता नहीं खुला। सूपड़ा साफ हो गया। ऐसा जनादेश कभी नहीं देखा।– उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में भाजपा सरकार है अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। अब घुसपैठ असंभव होने वाली है। गौ तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करेगी।

पंजाब के सांसद को आया अमित शाह का फोन! दिल्ली में मिलने के लिए कहा, राजकुमार चब्बेवाल ने पुलिस को दी शिकायत

होशियारपुर (पंजाब) ।

आम आदमी पार्टी के सांसद डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एक संदिग्ध फोन कॉल आई। सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8:45 बजे उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह उनसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने फोन पर खुद को अमित शाह बताते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और पूछा कि वह इस समय कहां हैं। डॉ. चब्बेवाल ने बताया कि उन्होंने कहा कि वह होशियारपुर में हैं। इस पर खुद को अमित शाह बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि जब भी वह दिल्ली आएं तो उनसे मुलाकात

करें। सांसद ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्हें शक हुआ क्योंकि फोन करने वाले की आवाज गृह मंत्री अमित शाह जैसी नहीं थी और न ही कॉल किसी आधिकारिक नंबर से आई थी। मामला संदिग्ध लगने पर उन्होंने तुरंत होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और संबंधित मोबाइल नंबर व कॉल की पूरी जानकारी देकर जांच करने को कहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तकनीकी जांच के जरिए कॉल करने वाले व्यक्ति और नंबर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध खेती और पशुपालन

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध खेती और पशुपालन से है। किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग कई महत्वाकांक्षी और लाभकारी अनुदान योजनाएं संचालित कर रहा है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इन राज्य स्तरीय योजनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (छस्ड) भी संचालित है, जो उद्यमिता विकास के तहत भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट पालन के लिए 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख) तक की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। इन्हीं लाभकारी सरकारी योजनाओं का सही उपयोग कर जनपद इटावा के ग्राम नगला केन्द्री निवासी श्री सुनील कुमार यादव ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से सफलता की एक नई इबारत लिखी है। हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त सुनील एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रारंभिक दौर में वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से पारंपरिक कृषि कार्यों पर निर्भर थे। पारंपरिक खेती से होने वाली सीमित आय और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण उनके सामने अक्सर आर्थिक चुनौतियां खड़ी रहती थीं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने और एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण की चाह में उन्होंने स्वरोजगार के नए अवसर तलाशने शुरू किए। इसी खोज के दौरान उनका रुझान कम निवेश और सीमित स्थान में अधिक लाभ देने वाले बकरी पालन व्यवसाय की ओर हुआ, जिसके लिए ग्रामीण परिवेश पूरी तरह से अनुकूल था। वर्ष 2023 में सुनील जी ने आत्मविश्वास के साथ मात्र 8-10 बकरियों के साथ बहुत ही छोटे स्तर पर यह कार्य शुरू किया। शुरुआती दिनों में अनुभव की कमी के कारण उन्हें उन्नत नस्ल के चयन, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन, सही पोषण और बाजार तक अपनी पहुंच बनाने जैसी कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि यह राह बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय निरंतर अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी संघर्षपूर्ण दौर में पशुपालन विभाग के माध्यम से उन्हें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए आवेदन प्रक्रिया से लेकर पूरी परियोजना के निर्माण तक में सुनील कुमार यादव का कदम-कदम पर साथ दिया। विभाग के सहयोग से उन्हें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (ब्ह्ल), मथुरा के वरिष्ठ विशेषज्ञों के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। इस प्रशिक्षण ने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया, जहां उन्हें उन्नत नस्लों की सटीक पहचान, बकरियों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार, मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन की गहरी तकनीकी समझ प्राप्त हुई। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सुनील जी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। वर्ष 2023 में ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत उनका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया। इस स्वीकृति के आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जसवंतनगर शाखा ने उनके उद्यम के लिए लगभग 8 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप 50 प्रतिशत का भारी अनुदान शामिल था। यह मजबूत वित्तीय सहायता उनके बकरी पालन व्यवसाय के लिए एक संजीवनी साबित हुई। सरकारी सहायता से मिली इस पूंजी का सदुपयोग करते हुए सुनील जी ने अपने फार्म का एक आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने बकरियों के रहने के लिए ऐसा वैज्ञानिक शेड बनवाया, जिसमें स्वच्छता, उचित वेंटिलेशन और जंगली जानवरों से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। चारे की समुचित व्यवस्था के लिए आधुनिक तरीके अपनाए, स्वच्छ पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की और पशु चिकित्सकों की सलाह पर नियमित टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण कराया। इन सभी व्यवस्थित और वैज्ञानिक उपायों के कारण बकरियों के स्वास्थ्य, उनके विकास और फार्म की कुल उत्पादकता में अभूतपूर्व सुधार हुआ। आज सुनील कुमार यादव का फार्म इलाके में आधुनिक पशुपालन का एक उत्कृष्ट मॉडल बन चुका है, जहां उच्च गुणवत्ता की उन्नत नस्लों का पालन पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ हो रहा है। वे बकरी के दूध, उनके पौष्टिक मांस और उन्नत नस्ल के बच्चों की बिक्री के माध्यम से सालाना लगभग 10 लाख रुपये की शानदार आय अर्जित कर रहे हैं, जो उनकी प्रारंभिक कृषि आय के मुकाबले कई गुना अधिक है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, इटावा और उनकी सक्रिय टीम से समय-समय पर मिलने वाले तकनीकी मार्गदर्शन और त्वरित पशु चिकित्सा सेवाओं ने उनके इस व्यवसाय को एक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहद मुनाफे वाले उद्यम में तब्दील कर दिया है। यह सफल महज एक किसान की व्यक्तिगत आर्थिक उपलब्धि की कहानी नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अंचलों में छिपी अपार संभावनाओं को सामने लाती है। अपनी बढ़ती आय के साथ-साथ सुनील जी ने अपने उद्यम में चार अन्य स्थानीय युवाओं को भी स्थायी रोजगार प्रदान किया है, जो गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने की दिशा में एक बेहद सकारात्मक और अनुकरणीय कदम है। वे लगातार अपने आस-पास के किसानों को आधुनिक तकनीकों के संवर्धन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। एक छोटे से गांव के साधनहीन किसान की यह उद्यमशीलता आज एक मिसाल बन गई है अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, सही वैज्ञानिक प्रशिक्षण और कल्याणकारी सरकारी नीतियों के माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भरता का एक सशक्त उदाहरण सबके सामने रखा है।

राजनीति का रक्त चरित्र

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई लेकिन चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों में सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जिसमें सत्ता में बैठने वालों ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसा को हथियार बनाया। चुनाव आते हैं, जाते हैं। जय-पराजय भी चलती रहती है लेकिन मौत का खेल लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई लेकिन खूनी सियासत ने पश्चिम बंगाल में सभी हदें पार कर दीं। पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह से लहूलुहान रही है। चुनाव आयोग द्वारा इस बार कड़े सुरक्षा प्रबंधों के चलते चुनावों के दौरान छिटपुट हिंसा की घटनाओं को छोड़कर कोई जनहानि नहीं हुई। इससे सभी ने राहत की सांस ली थी। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल कर ममता बनर्जी की 15 वर्ष पुरानी तृणमूल सरकार को उखाड़ फैंका। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी लेकिन चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया। बुधवार की रात भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने वाले शुभेन्दु अधिकारी के निजी सचिव चन्द्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की गई। उससे यह सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है कि क्या राज्य की सियासत का चरित्र बदलेगा या पूर्व की तरह ही चलता रहेगा। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में 2 भाजपा और 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और तोड़फोड़ और आगजनी का दौर जारी है। जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और जिस ढंग से अपने आप बुलडोजर चलाकर तृणमूल समर्थकों की दुकानों को ध्वस्त किया वह भी उतना ही निंदनीय है जितना की तृणमूल की गुंडागर्दी की निंदा की जाती है। शुभेन्दु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या के लिए यद्यपि भाजपा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को आरोपी करार दे रही है लेकिन फिलहाल निष्पक्ष जांच के बाद किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि क्या यह हत्या निजी रंजिश के चलते हुई है या इसके तार सियासत से जुड़े हुए हैं। इन हत्याओं ने भाजपा की जीत के जश्न को गुलाल की बजाय खून से रंग दिया है। अगर पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो यह एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां सियासी दुश्मनों को हराया नहीं जाता बल्कि खत्म कर दिया जाता है। बंगाल के गौरवशाली इतिहास और बौद्धिक संस्कृति को पहले 34 साल के कम्युनिस्ट शासन की सियासत ने धुंधला किया। गांव से लेकर कोलकाता के सत्ता के गलियारों तक पार्टी की सरकार थी और सरकार ही पार्टी। इसी कैडर कल्चर से राजनीतिक दुश्मनी ने जन्म लिया। कौन किसे वोट देगा यह लोग नहीं, पार्टी तय करती थी। एक पूरी पीढ़ी तक शासन करने वाली वामपंथी पार्टियों ने राजनीतिक हिंसा की नींव डाल दी। तीन दशक से भी ज्यादा के कम्युनिस्ट शासन में 20 हजार से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं की गई थी। कम्युनिस्टों ने हिंसा और गैर जिम्मेदार ट्रेड यूनियन वाद की वकालत और नेतृत्व करके पूंजीवाद को बंगाल से बाहर निकाल दिया और राज्य को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। इसी खूनी राजनीति के बीच एक उम्मीद बनकर उभरी ममता बनर्जी। लेफ्ट की हिंसक राजनीति को हराकर सत्ता में तो आईं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपना लिया। बंगाल की टीएमसी में कार्यकर्ता कितने थे पता नहीं, पर गुंडों की कोई कमी नहीं थी। 2018 का पंचायत चुनाव हो, 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा हो, या 2023 के पंचायत चुनाव के बाद का खून-खराबा, सब एक जैसा था। विरोधी पार्टियों के दफ्तरों में आग लगाना, लोगों के घरों में घुसकर टीएमसी को वोट देने की धमकी देना बंगाल में आम बात हो गई। गांवों में टीएमसी का विरोध करने वालों के पास दो ही रास्ते थे-या तो गांव छोड़ दो, या टीएमसी को वोट दो। टीएमसी का विरोध करने वालों को जहां-तहां पीटा गया, झूठे केसों में जेल में डाल दिया गया। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें खत्म कर दिया गया और उनके घर की महिलाओं पर अत्याचार किए गए। ममता के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे को भूल गई। ममता के राज में 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं, जबकि रेप के मामलों का तो कोई हिसाब ही नहीं। कई महिलाओं ने तो इज्जत के डर से पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा। उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि अगर वे शिकायत करने गईं तो सुरक्षित घर लौट पाएंगी। 2021 तक टीएमसी की खूनी राजनीति एक स्तर पर थी, लेकिन उसके बाद के हालात और भी भयानक हो गए। थोक में वोट पाने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाना और सिर्फ इसलिए हिंदुओं को निशाना बनाना क्योंकि उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, यह सब टीएमसी के गुंडों के जरिए चल रहा था। बंगाल के लोगों के सब्र का बांध टूटने में 15 साल लग गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में एक भी सीट न जीत पाने वाली बीजेपी, 2016 में 3 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी, आज 77 से 206 सीटें जीतने के स्तर पर आ गई है। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और न ही हिंसा को स्वीकार किया जा सकता है। भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा को समाप्त करना, आपराधिक तत्वों और गुंडा कल्चर को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती है।

नई सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भाले और राज्य के नागरिकों को भय मुक्त शासन दे। भाजपा कैडर को भी जोश के साथ होश में रहकर काम करना होगा और स्वयं भी किसी भी तरह के उपद्रव और हिंसा से दूर रहना होगा। हिंसा की जहरीली राजनीतिक संस्कृति अब खत्म होनी ही चाहिए।

सम्पादकीय...

हल्दीघाटी का अमर योद्धा –क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप

भारत के स्वर्णिम इतिहास में यदि अदम्य साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का कोई सर्वोच्च प्रतीक खोजा जाए, तो वह नाम है महाराणा प्रताप। यह नाम मात्र उच्चारण से ही मन में वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति का ज्वार उत्पन्न कर देता है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अडिग संकल्प के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ की वीरभूमि (वर्तमान राजस्थान) में हुआ। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे। उस समय मेवाड़ निरंतर संघर्षों से गुजर रहा था और चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। ऐसे कठिन समय में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। उनके सामने न केवल बाहरी आक्रमण का खतरा था, बल्कि आंतरिक चुनौतियाँ भी थीं। उनके राज्याभिषेक के समय उत्तराधिकार को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने एकमत होकर उन्हें ही योग्य शासक मानते हुए गद्दी सौंपी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने अनेक राजाओं को मित्रता और संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को भी संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उनके लिए स्वाभिमान सर्वोपरि था। वे जानते थे कि संधि का अर्थ पराधीनता स्वीकार करना है, जो उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध का वह ऐतिहासिक दिन आया, जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने-सामने हुईं। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। मुगल सेना संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित सेना थी, जिसमें राजपूतों के साथ भील योद्धाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। युद्ध अत्यंत भीषण और रक्तरंजित था। महाराणा प्रताप ने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए शत्रु सेना को कड़ी चुनौती दी। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक विजय में परिवर्तित नहीं हुआ, किंतु प्रताप की वीरता और संघर्षशीलता ने उन्हें अमर बना दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की स्वामीभक्ति और बलिदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय उदाहरण माने जाते हैं। वनवास, संघर्ष और पुनः विजय हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में रहकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा की। अंततः अपने जीवनकाल में उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः स्वतंत्र करा लिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, धैर्य और दृढ़ संकल्प से विजय प्राप्त की जा सकती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्ध और पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है।

जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के जरेरा टैंक के जीर्णोद्धार से किसानों को मिला पानी

-इंजेश सिंह

जनपद चित्रकूट के तहसील मानिकपुर के अंतर्गत आने वाला पाठा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण इलाका माना जाता है, जहाँ पथरीली भूमि, असमान स्थलाकृति तथा सीमित जल संसाधनों के कारण कृषि कार्य सदैव कठिन रहा है। इस क्षेत्र में स्थित जरेरा टैंक (तालाब), जिसका निर्माण कई वर्षों पूर्व स्थानीय किसानों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत के रूप में स्थापित हुआ था। लगभग 0.350 किलोमीटर लंबाई और 2.69 मिलियन क्यूबिक मीटर (डब्ड) जल भंडारण क्षमता वाला यह टैंक प्रारंभिक वर्षों में सिंचाई, पशुपालन तथा अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। समय के साथ यह टैंक क्षेत्रीय जल प्रबंधन का आधार बना था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसने इसकी उपयोगिता को लगभग समाप्त कर दिया। वर्षों के उपयोग और प्राकृतिक कारणों के चलते टैंक में भूमिगत सीपेज (ैममचंहम) की समस्या अत्यधिक बढ़ गई। टैंक वर्षा ऋतु में तो पूर्ण रूप से भर जाता था, परंतु चट्टानी संरचना में मौजूद सूक्ष्म एवं विस्तृत दरारों (त्वबा थ्पेेनतमे) के कारण पानी धीरे-धीरे जमीन के भीतर रिसने लगता था। परिणामस्वरूप, वर्षा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद जल स्तर तेजी से गिरने लगता था और नवंबर माह से पहले ही टैंक लगभग खाली हो जाता था। इस स्थिति का सीधा प्रभाव क्षेत्र के किसानों पर पड़ता था, विशेष रूप से रबी फसल के समय, जब सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पानी की अनुपलब्धता के कारण किसान सीमित क्षेत्र में ही खेती कर पाते थे, जिससे उनकी आय प्रभावित होती थी और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती थी। इसके साथ ही, लगातार जल रिसाव के कारण आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर भी गिरता जा रहा था, जिससे पेयजल संकट भी गहराने लगा था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराया गया। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि टैंक के अपस्ट्रीम क्षेत्र में चट्टानों के भीतर कई स्थानों पर अवपके और पिनतमे मौजूद हैं, जो जल के रिसाव के मुख्य कारण हैं। पारंपरिक उपाय, जैसे मिट्टी भराई या सतही मरम्मत, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक वैज्ञानिक एवं दीर्घकालिक समाधान अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के तहत सीमेंटेशियस ग्राउटिंग (ब्मउमदजपजपवने ळतवनजपदह) अथवा कर्टेन ग्राउटिंग (ब्नतजंपद ळतवनजपदह) तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया गया, जो जलाशयों में सीपेज नियंत्रण के लिए एक प्रभावी और प्रमाणित तकनीक मानी जाती है। कार्य के अंतर्गत टैंक के अपस्ट्रीम में 0.100 किलोमीटर से 0.300 किलोमीटर के बीच लगभग 200 मीटर लंबाई में ग्राउटिंग कार्य किया गया। इस प्रक्रिया में सबसे पहले निर्धारित क्षेत्र में तीन पंक्तियों (त्वू) में ड्रिलिंग की गई, जिनके बीच की दूरी लगभग 3-3 मीटर रखी गई।

प्रत्येक पंक्ति में 5-5 मीटर के अंतराल पर ड्रिल होल बनाए गए, जिनकी गहराई 4 मीटर तथा 7 मीटर (चट्टान के भीतर) तक रखी गई। इन होल्स को अल्टरनेट क्रम में तैयार किया गया, ताकि अधिकतम क्षेत्र को कवर किया जा सके और सभी संभावित दरारों तक सीमेंट स्लरी पहुँच सके। इसके बाद उच्च दबाव (त्मेनतम) के साथ सीमेंट स्लरी को इन होल्स में डाला गया, जिससे यह स्लरी चट्टानों की दरारों और खाली स्थानों में फैलकर उन्हें पूरी तरह भर सके। ग्राउटिंग की यह प्रक्रिया अत्यंत तकनीकी और सावधानीपूर्ण थी, क्योंकि इसमें सही दबाव, उचित मिश्रण अनुपात तथा सटीक ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। यदि इन मानकों का सही पालन न किया जाए, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इस कार्य के दौरान कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आईं। विशेष रूप से, अपस्ट्रीम क्षेत्र में अत्यधिक कीचड़ (ैसनी) होने के कारण ड्रिलिंग मशीनों को स्थापित करने और संचालित करने में कठिनाई हो रही थी। कई स्थानों पर ड्रिल होल स्थिर नहीं रह पा रहे थे, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए पहले कार्य स्थल से कीचड़ हटाया गया और उसके स्थान पर मिट्टी डालकर एक मजबूत आधार तैयार किया गया। इसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से ड्रिलिंग और ग्राउटिंग कार्य को आगे बढ़ाया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस वैज्ञानिक एवं सुनियोजित हस्तक्षेप के परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहे। जून 2024 तक टैंक में सीपेज नियंत्रण का कार्य लगभग पूर्ण रूप से सफल हो गया। अब टैंक में संचित जल लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगा है और अनावश्यक जल रिसाव में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहाँ टैंक नवंबर से पहले ही खाली हो जाता था, वहीं अब इसमें वर्ष भर या लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहने लगा है। इससे टैंक की जल धारण क्षमता में स्थायित्व आया है और यह पुनः एक विश्वसनीय जल स्रोत के रूप में स्थापित हो गया है। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्षेत्र के किसानों को प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत निही चिरईया सहित आसपास के गाँवों के कृषकों को अब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2024-25 में रबी फसल के दौरान कुल 1432 हेक्टेयर क्षेत्र में से 338 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की जा सकी, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। किसान अब अधिक क्षेत्र में खेती कर पा रहे हैं और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण और सामाजिक जीवन पर भी देखा गया है। टैंक में जल उपलब्धता बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर (ळतवनदकूंजमत समअमस) भी बढ़ा है, जिससे हैंडपंप और कुओं में पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है। क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है और सूखे की स्थिति में भी जल उपलब्धता बनी रहती है। पशु-पक्षियों, वन्य-जीवों के लिए भी यह टैंक एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बन गया है, जिससे जैव विविधता को भी लाभ मिला है। ग्रीष्म ऋतु में, जब जल संकट अपने चरम पर होता है, तब भी टैंक में जल उपलब्ध रहने से ग्रामीणों को राहत मिलती है। जरेरा टैंक का यह पुनरुद्धार केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह सतत जल प्रबंधन (ैनेजंपदंइसम ॅंजमत डंदंहमउमदज) का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सही तकनीक, उचित योजना और प्रभावी क्रियान्वयन को एक साथ जोड़ा जाए, तो पुरानी और निष्क्रिय जल संरचनाओं को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। कर्टेन ग्राउटिंग जैसी तकनीक न केवल सीपेज को नियंत्रित करने में सक्षम है, बल्कि यह जलाशयों की आयु और उपयोगिता को भी बढ़ाती है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव अन्य समान जलाशयों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से, ऐसे क्षेत्र जहाँ चट्टानी संरचना के कारण जल रिसाव की समस्या होती है, वहाँ इस तकनीक को अपनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यह मॉडल कम लागत में अधिक लाभ देने वाला है और इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है। जरेरा टैंक की यह सफलता की कहानी प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की किसान एवं गाँवों के नेतृत्व में जल संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिवर्तन ला रहे हैं। इस परियोजना ने न केवल एक जलाशय को पुनर्जीवित किया, बल्कि इससे जुड़े हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाया है। किसानों की बढ़ती आय, बेहतर कृषि उत्पादन, सुधरता हुआ पर्यावरण और स्थायी जल उपलब्धता-ये सभी इस पहल की सफलता के प्रमाण हैं। जरेरा टैंक आज एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है, जो यह सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा सार्थक परिणाम देता है।

अमेरिका-ईरान तनाव में ऐतिहासिक मोड़- युद्धविराम से समझौते की दहलीज तक- युद्ध पर लगेगा ब्रेक

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया की भू-राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है,जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब संभावित कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगभग 40 दिनों तक चले तीव्र सैन्य संघर्ष, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक व्यापार मार्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ा,ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गहरी चिंता में डाल दिया था। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जो विश्व के लगभग एक-तिहाई समुद्री तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है, संघर्ष का केंद्रीय बिंदु बन गया था। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता ने न केवल तेल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल पैदा किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर दिया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत जैसे ऊर्जा आयात- निर्भर देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई, जहाँ महंगाई और चालू खाता घाटे पर प्रत्यक्ष दबाव देखा गया।इसी पृष्ठभूमि में, 8 अप्रैल 2026 को लागू किया गया दो सप्ताह का अस्थायी युद्धविराम एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आया, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में आयोजित वार्ताओं के माध्यम से संभव हुई।यह पहल न केवल क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत थी,बल्कि इसने यह भी दर्शाया कि मध्यम शक्तियाँ भी जटिल वैश्विक संकटों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। 21 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का निर्णय इस बात का संकेत था कि दोनों पक्ष अब टकराव की बजाय संवाद को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता लौटाने और कूटनीतिक प्रक्रिया को समय देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।अब 6 मई 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार,दोनों देश एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब पहुँच चुके हैं, जो न केवल वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि एक व्यापक परमाणु समझौते की रूपरेखा भी तय करेगा। यह संभावित समझौता वैश्विक कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है, क्योंकि यह वर्षों से चले आ रहे अविश्वास,प्रतिबंधों और सैन्य टकराव के चक्र को तोड़ने का अवसर प्रदान करता है। यदि यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक संतुलन को भी एक नई सटीक दिशा देगी। साथियों बात अगर हम युद्ध पर लगेगा ब्रेक ईरान- अमेरिका समझौते की दहलीज पर खड़ी दुनिया में शांति की नई उम्मीद इसको समझने की करें तो 6 मई 2026 की वैश्विक कूटनीतिक तस्वीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है,जहाँ पिछले कुछ महीनों से मध्य पूर्व में सुलग रही आग अब शांत होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से जारी सैन्य टकराव ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को गहरे संकट में डाल दिया था,बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे इस संघर्ष के संभावित अंत की ओर इशारा करते हैं। दोनों देश एक एक-पेज के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति के करीब पहुँच चुके हैं, जिसे यदि अंतिम रूप मिल जाता है,तो यह 2026 के इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। साथियों बात अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलूपहलू को समझने की करें तो यह है कि यह समझौता केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है,बल्कि इसमें दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता के तत्व भी शामिल हैं। प्रस्तावित समझौते के अनुसार, दोनों देश मध्य पूर्व में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा करेंगे,जो पिछले दो महीनों में कई स्तरोंपर बढ़ता गया था। इस संघर्ष के दौरान समुद्री मार्गों पर हमले, ड्रोन स्ट्राइक, और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की घटनाएँ सामने आईं, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों, विशेष रूप से तेल आपूर्ति, पर गहरा असर पड़ा। ऐसे में युद्धविराम की संभावना अपने आप में एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। साथियों बात अगर हम इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम को समझने की करें तो वह है होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा मुद्दा।यह जलमार्ग विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है,जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है। संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर नाकाबंदी और हमलों ने तेल की कीमतों को अस्थिर कर दिया था और वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।अब प्रस्तावित समझौते के तहत दोनों देश इस जलडमरूमध्य को चरणबद्ध तरीके से खोलने और जहाजों की सुरक्षित आवाजा ही सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। यह न केवल ऊर्जा बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि वैश्विक व्यापारिक विश्वास को भी बहाल करने में मदद करेगा। साथियों बात अगर हम तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है इसको समझने की करें तो, ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन को 15 वर्षों तक रोकने और परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव 2015 के परमाणु समझौते की याद दिलाता है, जिसे बाद में अमेरिका ने एकतरफा रूप से छोड़ दिया था।

इस बार दोनों पक्ष अधिक सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं।अमेरिका की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि वह ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और उसकी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को वापस करने के लिए तैयार है। यह कदम ईरान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण व बिलकुल सटीक भूमिका निभा सकता है। साथियों हालांकि,इस संभावित समझौते की राह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देशों के बीच कुल 14 मुद्दों पर बातचीत चल रही है, जिनमें से दिनांक 6 को 2026 को केवल 3 पर सहमति बनी है, जबकि 11 मुद्दों पर अभी भी मतभेद कायम हैं। इन मुद्दों में क्षेत्रीय प्रभाव, मिसाइल कार्यक्रम,और निरीक्षण व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि भले ही एक प्रारंभिक समझौता निकट हो, लेकिन स्थायी शांति के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है।उन्होंने एक ओर जहाँ ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य और आर्थिक कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान की दिशा में भी पहल की।

प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक अभियान को अस्थायी रूप से रोकने का उनका निर्णय इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब टकराव की बजाय बातचीत को प्राथमिकता देना चाहता है। हालांकि, ट्रंप के बयानों में अब भी आक्रामकता झलकती है, जैसे उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह द्वंद्वात्मक रणनीति दबाव और संवाद का मिश्रणअमेरिकी विदेश नीति का एक परिचित पैटर्न है। ईरान की ओर से भी लचीलापन दिखाया गया है,जो इस बात का संकेत है कि वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से बचनाचाहता है।आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, और ऐसे में प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए वह कुछ शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई देता है। हालांकि, ईरान के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखे, जो बातचीत को जटिल बनाता है। साथियों बात अगर हम इस संभावित समझौते का वैश्विक प्रभाव को समझने की करें तो यह है भी अत्यंत व्यापक होगा। सबसे पहले, ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आएगी, जिससे तेल और गैस की कीमतों में गिरावट संभव है। इससे उन देशों को राहत मिलेगी जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं,जैसे भारत,जापान और यूरोपीय देश।दूसरा, वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम कारक होती है। तीसरा, यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है, जहाँ दो विरोधी देश संवाद के माध्यम से समाधान तक पहुँचते हैं।

साथियों बात अगर हम इस पूरे समझौते को भारत के संदर्भ में देखेंतो यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है,और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिरता उसके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।इसके अलावा, भारत के लाखों प्रवासी इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा भी इस संघर्ष से प्रभावित होती है। ऐसे में यदि यह समझौता सफल होता है,तो भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर लाभ होगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे समझौते अक्सर नाजुक होते हैं। 2015 का परमाणु समझौता भी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था,लेकिनराजनैतिक बदलावों और आपसी अविश्वास के कारण वह टिक नहीं सका।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

चार दशकों से निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को समर्पित वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का भव्य सम्मान

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह)पत्रकारिता जगत में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठ और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार के आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी को उनकी चार दशकों से अधिक की उत्कृष्ट, निर्भीक एवं जनपक्षधर पत्रकारिता सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अपने लंबे पत्रकारिता करियर में आशुतोष चतुर्वेदी ने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों – प्रभात खबर, अमर उजाला, माया, इंडिया टुडे, संडे ऑब्जर्वर, दैनिक जागरण और बीबीसी लंदन – में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अहम असाइनमेंट्स को सफलतापूर्वक कवर किया। राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश यात्राओं की रिपोर्टिंग में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में भी उनका विशेष योगदान रहा। बीबीसी हिंदी वेबसाइट के लॉन्च में उनकी अहम भूमिका को पत्रकारिता जगत की बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर, मोमेंटो और स्मारिका भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि आशुतोष चतुर्वेदी ने अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में निष्पक्षता, साहस और मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया कई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में आशुतोष जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने में आशुतोष चतुर्वेदी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। समाज और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाकर उन्होंने पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को मजबूत किया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सुरेन्द्र कुमार बने उपाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

नई दिल्ली। (साहिल गौड़) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक ,सुरेन्द्र कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है। उनकी नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार लंबे समय से कांग्रेस संगठन एवं जनसेवा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक सरोकारों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें दी गई नई जिम्मेदारी से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अवसर पर किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी एवं रिपब्लिकन मजदूर संगठन की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार के नेतृत्व एवं अनुभव से दिल्ली कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और पार्टी संगठन को नई दिशा प्राप्त होगी। रिपब्लिकन मजदूर संगठन के महासचिव एवं पत्रकार विजय कुमार भारती ने कहा कि श्री सुरेन्द्र कुमार की नियुक्ति संगठनात्मक क्षमता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली में और अधिक सशक्त होकर जनता के मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया तथा श्री सुरेन्द्र कुमार के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

हाईवे पर ट्रकों की मनमानी बनी मौत का रास्ता-विजय शंकर चतुर्वेदी ने नितिन गडकरी से की सख्त कार्रवाई की मांग

दिल्ली। (आकाश शक्य) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती अव्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रख्यात समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कड़े और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ट्रकों की मनमानी आवाजाही अब आम लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। भारी वाहन सभी लेनों में चलते हैं, ओवरटेक करते हैं और कई बार छोटे वाहनों को घंटों जाम और जोखिम भरी स्थिति में फंसा देते हैं।

विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि देश के एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इन सड़कों पर ट्रकों की अनुशासनहीनता के कारण आम वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहन चालकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक बनती जा रही है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग करते हुए कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ट्रकों के लिए अलग और निश्चित लेन निर्धारित की जाए। ड्रहकों को केवल निर्धारित लेन में ही चलने की अनुमति हो और इसका सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि भारी ट्रक बीच और फास्ट लेन तक में चलते हैं, जिससे छोटे वाहनों की गति रुक जाती है और दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

चतुर्वेदी ने यह इुद्यह्यम मांग की कि नियम तोड़ने वाले ट्रक चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पहली गलती पर भारी जुर्माना, दूसरी बार लाइसेंस निलंबन और लगातार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाए। इसके साथ ही ट्रक मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाए और बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों को जब्त करने की व्यवस्था लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि सख्त क्रियान्वयन से सुनिश्चित होती है। यदि सरकार ट्रकों की लेन व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाए और तकनीकी निगरानी बढ़ाए, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने हाईवे पर सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक चालान सिस्टम और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की।

विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि सड़क पर अनुशासन केवल सुविधा का नहीं बल्कि जीवन रक्षा का विषय है। हर दिन होने वाली दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसका एक प्रमुख कारण भारी वाहनों की लापरवाही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तुरंत नई नीति लागू की जाए, ताकि देश के हाईवे सुरक्षित, व्यवस्थित और भयमुक्त बन सकें।

दिल्ली कांग्रेस संगठन को मिली नई मजबूती- अनिल भारद्वाज बने महासचिव (संगठन)

नई दिल्ली। (आकाश शक्य)ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अनुशंसा तथा एआईसीसी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद की गई।

नियुक्ति संबंधी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति दिल्ली पीसीसी प्रभारी एवं विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन द्वारा जारी की गई। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता, सौम्य व्यक्तित्व और मजबूत जनसंपर्क के लिए पहचाने जाने वाले अनिल भारद्वाज लंबे समय से कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। एक मृदुभाषी, मिलनसार और जन-जन में लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। दिल्ली कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। संगठनात्मक अनुभव, राजनीतिक समझ और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल उनकी विशेषता रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महासचिव (संगठन) के रूप में उनकी नियुक्ति से दिल्ली कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी के विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों ने अनिल भारद्वाज को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे संगठन हित में एक सकारात्मक कदम बताया है। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने अनिल भारद्वाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ÷अनिल भारद्वाज एक अनुभवी, कर्मठ और जमीनी नेता हैं। उनका सरल स्वभाव, संवाद क्षमता और कार्यकर्ताओं से आत्मीय जुड़ाव उन्हें विशेष बनाता है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस संगठन को नई दिशा और नई गति मिलेगी।÷ उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन को ऐसे अनुभवी और जनप्रिय नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मजबूत संवाद स्थापित कर सके। अनिल भारद्वाज निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और प्रभावशीलता के साथ निभाएंगे। दिल्ली कांग्रेस में इस नियुक्ति को आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठन विस्तार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली कांग्रेस को मिला मजबूत नेतृत्व-सुरेन्द्र कुमार बने उपाध्यक्ष

नई दिल्ली।(साहिल गौड़) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों में हर्ष की लहर है। उनकी नियुक्ति को संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार लंबे समय से जनसेवा, संगठन निर्माण एवं समाज के हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव, मिलनसार व्यक्तित्व और जमीनी पकड़ का लाभ दिल्ली कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके

नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। इस अवसर पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी तथा किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजय कुमार ने श्री सुरेन्द्र कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कांग्रेस संगठन के लिए सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री सुरेन्द्र कुमार अपने अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से संगठन को नई मजबूती प्रदान करेंगे तथा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे।कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों एवं पत्रकार जगत से जुड़े लोगों ने भी श्री सुरेन्द्र कुमार के उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की कामना की है।

प्रख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. भीमसेन बंसल की आठवीं पुण्यतिथि पर चिकित्सा जगत और कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह)देश के प्रसिद्ध चिकित्सक, आर.जी. स्टोन हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं समाजसेवा के पर्याय माने जाने वाले स्वर्गीय डॉ. भीमसेन बंसल की आठवीं पुण्यतिथि पर चिकित्सा जगत, सामाजिक क्षेत्र और कांग्रेस परिवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके द्वारा समाज और चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें सच्चा मानवसेवी और जननायक बताया गया।

डॉ. भीमसेन बंसल ने अपने जीवनकाल में लाखों मरीजों का सफल पथरी ऑपरेशन कर उन्हें नई जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें देशभर में विशेष पहचान दिलाई। वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सदैव सहायता हेतु तत्पर रहते थे तथा अनेक मरीजों का निःशुल्क उपचार कर मानवता की मिसाल कायम की।

चिकित्सक होने के साथ-साथ डॉ. बंसल एक सक्रिय समाजसेवी और लोकप्रिय जननेता भी थे। वे दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा दो बार निगम पार्षद रहे। कांग्रेस संगठन में उनकी पहचान एक मजबूत स्तंभ, कर्मठ नेता और जनसेवा के

प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व के रूप में रही। उन्होंने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में हमेशा आमजन की आवाज उठाई और जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता दी।

उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक और चिकित्सा जगत की अनेक हस्तियों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हु

डॉ. भीमसेन बंसल को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जय प्रकाश अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मिर्जा जावेद अली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रभारी डॉ. चंचल अग्रवाल, कूचा पंडित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय यादव, पूर्व निगम पार्षद कृष्णा मुरारी जाटव, पूर्व निगम पार्षद डॉ. आर.बी. सिंह तथा आशीष हरीचंद वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने भी स्वर्गीय डॉ. भीमसेन बंसल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ÷डॉ. बंसल का सामाजिक एवं मानवीय योगदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। उन्होंने अपने सेवा भाव, विनम्रता और समर्पण से समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।÷

शादी की तैयारियों के बीच घर खाली करने का नोटिस, यमुना बाजार के लोगों ने सरकार से लगाई गुहार

नई दिल्ली। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में इन दिनों लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल है. यमुना किनारे बसे इस इलाके में रहने वाले पंडा-पुजारी, नाविक और दूसरे परिवारों को सरकार की तरफ से घर खाली करने का नोटिस दिया गया है. 5 मई को जारी हुए इस नोटिस में लोगों से 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है. इस कार्रवाई के बाद यहां रहने वाले परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. सबसे ज्यादा दर्द उस परिवार में देखा जा रहा है जहां 10 मई को बेटी की शादी होनी है. शादी की तैयारियों में जुटा परिवार अब घर बचाने की चिंता में डूब गया है. परिवार का कहना है कि शादी की खुशियां अचानक गम में बदल गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से यहां रह रहे हैं. कुछ लोग पूजा-पाठ कर परिवार चला रहे हैं तो कुछ नाव चलाकर या मुंडन संस्कार कर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं. लोगों का कहना है कि अचानक से घर खाली करने का आदेश देना ठीक नहीं है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमारी कई पीढ़ियां यहां रही हैं. 15 दिनों में हम कहां जाएंगे? यही हमारा घर है, यही हमारा काम है और यही हमारी जिंदगी है. इलाके के लोगों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें हटाना चाहती है तो पहले रहने की दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए. लोगों ने मांग की है कि सरकार उन्हें सिर छुपाने के लिए छत दे, उसके बाद ही यहां से हटाने की बात करे. लोगों का कहना है कि वे इस मामले को लेकर एलजी और सरकार से बातचीत कर रहे हैं. अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. दरअसल, यमुना किनारे बसे इस इलाके में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है. जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है, सबसे पहले इन्हीं घरों में पानी भरता है. इसी वजह से सरकार इस इलाके को खाली कराना चाहती है ताकि बाढ़ के दौरान किसी तरह की जनहानि न हो. पिछले साल 2025 में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में करीब पांच फीट तक पानी भर गया था. उस समय लोगों को अपने घर छोड़कर राहत कैंपों में रहना पड़ा था. उस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इलाके का दौरा किया था और मदद का भरोसा दिया था. अब जिस तरह से लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है, उससे इलाके में नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोग खुद को बेघर होने के डर में जी रहे हैं. वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

नोएडा हिंसा मामला - हाईकोर्ट जाइए, यहां पहले ही 93000 केस लंबित, शीर्ष कोर्ट का छात्रा को जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा में 13 अप्रैल को हुए मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार एक छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आकृति चौधरी की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएं। पीठ ने कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? हर कोई अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करके यहां आता है। सुप्रीम कोर्ट में 93 हजार मामले पहले से ही लंबित हैं। आकृति चौधरी के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए और जमानत की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि आकृति चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। शीर्ष कोर्ट ने केशव आनंद नाम के व्यक्ति की याचिका पर पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। नोएडा की एक कोर्ट ने पहले तीन महिलाओं आकृति चौधरी, मनीषा चौहान और सृष्टि गुप्ता की शर्तों के साथ पुलिस रिमांड की अनुमति दी थी। इन पर 13 अप्रैल के औद्योगिक मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान उनके वकीलों को मौजूद रहने की अनुमति होगी। आकृति चौधरी और सृष्टि गुप्ता दोनों दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी उम्र 20 के आसपास है। चौधरी ने दौलत राम कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर किया है, जबकि मनीषा नोएडा की एक औद्योगिक इकाई में काम करती हैं। पुलिस ने हिरासत के लिए दायर आवेदन में कहा था कि आरोपियों के घर से अहम साक्ष्य मिलने की पूरी संभावना है।

नोएडा में पिछले महीने फैक्टरी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, कई औद्योगिक इकाइयों के मजदूर लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग को लेकर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। हालांकि, यह प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने कथित तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पत्थर फेंके और एक वाहन में आग लगा दी।

इतना न उछलो बीजेपी वालों, अहंकार तो..., फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह

नई दिल्ली।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अपने साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है. अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. आप सांसद ने कहा है कि इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो? आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-÷ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में? लोकसभा की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ प्लेन में अभद्रता ये साबित करता है की बीजेपी का अहंकार चरम पर है. इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नही चला तो तुम क्या चीज हो? बेईमानी से चुनाव जीत कर इतना न उछलो बीजेपी वालों. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6ई-719 से दिल्ली यात्रा कर रही थीं. उनके अनुसार, वह विमान की सीट 1एफ पर बैठी थीं, तभी 4 से 6 लोगों का एक समूह विमान में सवार हुआ. टीएमसी सांसद का आरोप है कि ये लोग लगातार उन्हें घूरते रहे और बाद में विमान के पिछले हिस्से की ओर चले गए. उन्होंने कहा कि फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने के बाद, लेकिन विमान का दरवाजा खुलने से पहले, इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसके साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस घटना को उनकी सुरक्षा और निजी गरिमा का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसे जनता का गुस्सा÷ बताना गलत होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी हरकत थी, जिसका उद्देश्य उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना था.

बार आपका इंतजार कर रहा है, महिला वकील की याचिका खारिज कर सीजेआई सूर्यकांत ने सुनाया दिलचस्प निजी किस्सा

नई दिल्ली।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को अदालत में एक दिलचस्प निजी अनुभव साझा करते हुए न्यायिक सेवा अभ्यर्थी को भविष्य के लिए प्रेरित किया। दरअसल, न्यायिक सेवा परीक्षा की अभ्यर्थी प्रेरणा गुप्ता अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अपना निजी अनुभव साझा कर माहौल को भावुक बना दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि जब वह कानून की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने भी न्यायिक सेवा के लिए आवेदन

किया था। उस समय अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते थे। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में बदलाव के बाद हाई कोर्ट के जजों की राय निर्णायक हो गई थी। सीजेआई ने बताया कि उसी दौरान उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। इंटरव्यू पैनल में शामिल एक वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें पहले से जानते थे, क्योंकि वह उनके समक्ष दो महत्वपूर्ण मामलों में बहस कर चुके थे। सीजेआई ने बताया कि एक दिन उस न्यायाधीश ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर पूछा कि क्या वह न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं। उनके हां कहने पर न्यायाधीश ने तुरंत उन्हें बाहर जाने को कह दिया। सीजेआई ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा कि उनके सारे सपने टूट गए हैं और उनका करियर खत्म हो गया। हालांकि अगले दिन वही न्यायाधीश फिर मिले और उन्होंने सलाह दी कि अगर वह न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह वकालत जारी रखें क्योंकि बार उनका इंतजार कर रही है।

सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में शामिल न होने का फैसला किया और पूरी तरह वकालत पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अदालत में मौजूद याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनका वह फैसला गलत था। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थी को भविष्य में उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा देने और आगे बढ़ने की सलाह दी। याचिका खारिज होने के बावजूद प्रेरणा गुप्ता अदालत से मुस्कुराते हुए बाहर निकलीं।

गर्मी का इलाज, जेब में रखो प्याज, दिल्ली के Heat Action Plan पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के लू अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज रखो की लू कार्य योजना की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का यह तंज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस पुराने नुस्खे पर था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे गर्मी के चरम मौसम में अपनी जेब में प्याज रखते हैं ताकि गर्मी से राहत पा सकें। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग के नारे के साथ देश की राजधानी के लिए एक हीट एक्शन प्लान की घोषणा की है। दरअसल, उनके भाजपा सहयोगी और मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज रखो के नारे के साथ हीट एक्शन प्लान शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना स्थित अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि आज के युग में हर कोई फोन रखता है, लेकिन वह प्याज रखते हैं, क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए अपनी जेब से एक प्याज निकाला, जिससे वहां मौजूद लोग खूब हंसे। सिंधिया ने कहा कि मैं अपनी कार में एसी नहीं चलाता, मैं बस अपनी जेब में एक प्याज रखता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री ने आगे कहा कि अपनी जेब में एक प्याज रखिए; 51 डिग्री की गर्मी में भी कुछ नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में 48 घंटे में 482 अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी और एनसीआर में सक्रिय संगठित अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ अब तक का बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत 48 घंटे तक लगातार छापेमारी की. 5 मई सुबह 8 बजे से शुरू हुआ यह ऑपरेशन 7 मई सुबह 8 बजे तक चला. जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस ने 1014 ठिकानों पर रेड मारी और कुल 482 अपराधियों व गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, नकदी, नशीले पदार्थ, शराब और वाहन भी बरामद किए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बार ऑपरेशन में सिर्फ गैंगस्टरों को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया गया. इसमें शूटर्स, हथियार सप्लायर, फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले, फाइनेंसर, वाहन उपलब्ध कराने वाले सोशल मीडिया हैंडलर और ठिकाने देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई.

शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर सबसे बड़ा वार

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान समर्थित और ISI से जुड़े बताए जा रहे शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर कार्रवाई रही. पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को जोड़कर उन्हें देश

विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था. इन लोगों से सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई कराने और टारगेट किलिंग जैसे काम कराए जा रहे थे. स्पेशल सेल ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और गुजरात के आरोपी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करने का टास्क दिया गया था. कुछ आरोपी हथियार तस्करी में भी शामिल थे.

नंदू गैंग समेत कई बड़े गैंग्स पर शिकंजा

ऑपरेशन के दौरान कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए. इसके अलावा काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, टिल्लू, कौशल चौधरी, सद्दाम गौरी और अन्य गैंग्स के सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई. पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सबसे यादा 443 गिरफ्तारियां दूसरे छोटे-बड़े गैंग्स से जुड़े अपराधियों की हुई हैं.

भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद

इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 141 पिस्टल, 212 कारतूस, 79 चाकू, 24 वाहन ,करीब 19 लाख रुपये नकद, 19 किलो नशीला पदार्थ ,1234 शराब की बोतले बरामद किए है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जेलों और विदेशों में बैठे गैंग सरगनाओं के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए